14 अध्याय

केन्द्रीय योजनाएं, परियोजनाएं तथा कार्यक्रम/मिशन

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- भारत सरकार द्वारा जनता के सामाजिक–आर्थिक लोक कल्याण कि योजनाएं के उद्देश्य क्या–क्या हैं ?

तालिका 14.1ः केन्द्रीय योजनाएं, परियोजनाएं तथा कार्यक्रम/मिशन

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
1.	भारत क्यू आर कोड	21 फरवरी, 2017	नगद रहित कारोबार हेतु	• विकास एनपीसीआई, मास्टर कार्ड एवं वीजा द्वारा। • विश्व का प्रथम इंटरॉपरेबल पेमेण्ट एकसप्टेंस साल्यूशन है। • एक ही प्लेटफार्म पर भुगतान की सुविधा। • टास्क पर सूचनाओं को संजोए रखता है।
2.	राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन	30 जून, 2017	केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा	• विश्व बैंक के सहयोग से प्रारम्भ फ्लैग शिप कार्यक्रम। • स्वदेशी विनिर्माण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले आवश्यक परितंत्र के निर्माण में सहायक। • जीवन रक्षक दवा के उत्पादन, अनुसंधान को बढ़ावा। • वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजर में भारत का महज 2.8 प्रतिशत योगदान है इस नयी योजना से 5 प्रतिशत होने का अनुमान।
3.	भारत का संस्क्रमि मानचित्रण राष्ट्रीय मिशन	17 जून, 2017	केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा	• पंडित दीन दयान उपाध्याय की जन्मभूमि मथुरा से। • सांस्कृति प्रतिभा को पोषित करना। • सांस्कृति विरासत व इसका संरक्षण करना। • ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा खोज प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जायेगा। • कलाकारों एवं लेखकों को विभिन्न आयोजनों में शामिल होने पर ए, बी, सी श्रेणी प्रदान कि जायेगी।

(Continued)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
4.	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	8 फरवरी, 2017	ग्रामीण डिजिटल साक्षरता हेतु	• 6 करोड़ लोगों को 2017 तक डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य। • मार्च-2019 तक ग्रामीण भारत को डिजिअल साक्षरता में प्रवेश कराने हेतु 2351 करोड़ रूपये के व्यय की घोषणा। • यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। • एनएसएसओ के अनुसार मात्र 6 प्रतिशत ग्रामीणों के पास कम्प्यूटर है।
5.	राष्ट्रीय सुस्थिर पर्यावास मिशन	2017	जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा	• वनों में ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। • शहरी आयोजन। • पुनः चक्रण और विद्युत उत्पादन सहित ठोस और तरल समुन्नत प्रबंधन। • सार्वजनिक परविहन के मॉडल को विकसित करना। • भवनों की अर्जामता बढ़ाने हेतु प्रयास करना। • चरम मौसमी घटनाओं के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणालियों का सुधार करना।
6.	विद्यांजली योजना	जून, 2016	विद्यालय में स्वैच्छिक कार्यक्रम हेतु	• सर्व शिक्षा अभियान के तहत। • इसके तहत अप्रवासी भारतीय, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवा निवृत सरकारी अधिकारी इत्यादि स्कूलों में स्वैच्छिक योगदान दे सकते है।
7.	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	1 अप्रैल, 2017	सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय द्वारा	• उम्र संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे बीपीएल बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। • इसमें प्रत्येक जिले में 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें होंगी।
8.	साथ कार्यक्रम	10 जून, 2017	नीति आयोग द्वारा प्रारंभ मावन पूंजी के रूपांतरण हेतु	• शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प मकनीकी सहायता से करना है। • इसमें राज्य तीन भावी रोल मॉडलों का चयन करेंगे। • इसमें राज्यों के चयन का आधार प्रसूति मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर, मलेरिया के मामले आदि है।
9.	वात्सल्य मातृ अमृत कोष मानव दुग्ध बैंक	7 जून, 2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा	• दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। • यह एक राष्ट्रीय मानव (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केन्द्र है। • इसकी स्थापना नार्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय और नीपी नार्वे इंडिया पार्टनर इनिशियेटिव के सहयोग से हुई है।
10.	प्रवासी कौशल विकास योजना	9 जनवरी, 2017	यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों विदेश मंत्रालय व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी।	• प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14वें प्रवासी भारतीय दिवस (बंगलूरू, कर्नाटक) में इस योजना का शुभारम्भ किया। इय योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(Continued)

तालिका 14.1: केन्द्रीय योजनाएं, परियोजनाएं तथा कार्यक्रम/मिशन *(Continued)*

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
11.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	1 सितम्बर, 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश जारी किये **घोषणा**—31 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ***नोट***—विकास मंत्री मेनका गाँधी ने योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश जारी किये ***नोट***—प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी, 2018 से इस योजना के संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन की घोषणा की थी।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा	• 1 जनवरी, 2018 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5000 रुपये की नकद प्रोतसाहन राशि सीधे उनके खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
12.	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2017 को इस योजना की घोषणा की जो कि औपचारिक रूप से वित्त मंत्री ने 21 मई, 2017 को लांच की। जिसे मार्च 2020 तक बढाया गया है।		• 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। यह योजना 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक रिटर्न सुनिशिचत करता है।

(Continued)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
13.	नाविका सागर परिक्रमा कार्यक्रम	10 सितम्बर, 2017	रक्षा मंत्रालय	• भारतीय नौसेना द्वारा देश में महिला सशक्तीकरण और महासागर नौकायन को बढ़ावा देना है। • विश्व मंच पर नारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। • नौकायान के द्वारा पर्यावरण अनुकूल गैर-परम्परागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। • स्वदेश निर्मित आईएनएस तारिणी पर नौकायन करके 'मेक इन इंडिया' की सफलता को दर्शाना है। • समुद्र में प्रदूषण की निगरानी कर रिपोर्ट तैयार करना। • महासागर नौकायन को बढ़ावा देने के लिए चालक दल विभिन्न बंदरगाह पड़ावों पर भारतीय मूल के स्थानीय व्यक्तियों से वार्ता करेंगें।
14.	एक धरोहर गोद लो योजना	27 सितम्बर, 2017	संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ	• निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों और कर्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक स्थलों को गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के माध्यम से स्मारकों और पर्यटन स्थलों के स्थायी बनाने का दायित्व देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। • आतिथ्य यात्रा व बैंकिग क्षेत्र की 7 कम्पनियों को स्मारक मित्र' के रूप पर्यटन मत्रालय द्वारा **चयनित** किया गया है। इन 7 **कम्पनियों** को 25 अक्टूबर 2017 को केन्द्र सरकार के पर्यटन पर्व के अन्तिम दिन आशय पत्र (Letters of Intent) प्रदान किये गये। **चयनित 7 कम्पनियां (गोद दिये गये पर्यटन स्थल)** **(i) SBI Foundatuion** 1. जतंर-मंतर (दिल्ली) **(ii) TK international Limited** 1. कोणार्क का सूर्य मंदिर (ओडीसा), 2. राजा रानी मंदिर (भुवनेश्वर), 3. रत्नागिरी स्मारक (जयपुर), 4. रत्नागिरी स्मारक (ओडीसा), **(iii) Yatra Online Pvt. Limited** 1. हम्पी (कर्नाटक), 2. लेह-पैलेस (जम्मू-कश्मीर) 3. कुतुबमिनार (दिल्ली), 4. अंजता गुफा (महाराष्ट्र), **(iv) Travel Corporation of India Ltd.** 1. मत्तनचेदी पैलेस संग्राहलय (कोच्चि), 2. सफदरजंग मकबरा (दिल्ली),

(Continued)

तालिका 14.1: केन्द्रीय योजनाएं, परियोजनाएं तथा कार्यक्रम/मिशन (Continued)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
				(v) Adventure Tour Operator Association of India 1. गंगोत्री मंदिर क्षेत्र व गोमुख तक के मार्ग (उत्तराखण्ड), 2. माउण्ट स्टोक कांगरी (लद्दाख, जम्मू कश्मीर) **(vi) Special Holiday Travel Pvt. Ltd. (with) Rotary Club of Delhi.** 1. अग्रेसन की बावड़ी (दिल्ली) **(vii) NBCC (National Buildings Construction Corporation Limited)** 1. दिल्ली के पुराने किले। ***नोट***—इस योजना के जरिये देशभर के स्मारकों, धारोहरों और पर्यटन स्थलों को विकसित कर पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन सम्भावना तथा सांस्कृतिक महत्व को बढावा दिया जायेगा।
15.	रो-रो फेरी सर्विस	22 अक्टूबर, 2017 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात से		• सागरमाला परियोजना (14 अप्रैल, 2016 में प्रारम्भ) जिसके अन्तर्गत बंदरगाहो का विकास तथा बंदरगाहों तक सामानों को त्वरित, कम लागत व कुशलतापूर्वक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना था, के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रो-रो फेरी सर्विस प्रारम्भ की गयी है। • रो-रो सेवा के माध्यम से बड़े ट्रको को सीधे एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक पहुंचाने के लिये जहाजों का प्रयोग किया जायेगा, जो पहले सड़क मार्ग से पहुंचाये जाते थे। अर्थात् रो-रो फेरी सर्विस का संचालन धोधा बन्दरगाह से दहेज बन्दरगाह तक होगा। इन बंदरगाहों का विकास सागरमाला परियोजना के तहत किया गया है। • सड़क मार्ग से जो दूरी 360 किमी थी उसे बंदगाह विकसित कर जहाज/बोट द्वारा मात्र 31 किमी दूरी तय करनी पड़ेगी। • समय व परिवहन लागत दोनों में कमी आयेगी। • ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा क्योंकि सामान से लदी से ट्रक सड़क मार्ग के स्थान पर जलमार्ग से अपने गनत्व्य स्थान पहुंचेगी। • सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी • परिवहन लागत में कमी वस्तु के मूल्य को कम करने में सहायक होगी, जो मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी। • परिवहन लागत में कमी उत्पादक वर्ग के लाभ को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। • ट्रकों के संचालन में कमी आने से वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित करने में सहयोग मिलेगा।

(Continued)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
				• कम समय अवधि में वस्तुओं के अपने गंतव्य स्थल में पहुंचने से खाद्य सामग्रियों का अपव्यय में कमी आयेगी। *नोट*—धोधा बन्दरगाी भावनगर जिले में स्थित है, जबकि दहेज बंदरगाह भरूच जिले में स्थित है।
16.	सघन मिशन इन्द्रधनुष योजना	8 अक्टूबर, 2017 24 दिसंबर, 2014	प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात से	• 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं कोटीकाकरण अभियान से जोड़ना है ताकि माता व शिशु के स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सके। यह योजना मुख्य रूप से उनके लिये है जो, सरकार के परम्परागत टीकाकरण अभियान से जुड़ नहीं सके। • इस अभियान के तहत देश के 16 राज्यों के 121 जिलों तथा 17 शहरों के साथ 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों में प्रत्येक माह में 7 दिन (7 से 14 तारीख) के लिए चलाया जायेगा। • इस अभियान में वर्ष 2020 तक कम से कम 90% शिशुओं तथा माताओं को टीकरण प्रतिरक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। • यह अभियान 4 चरणों अर्थात् (i) अक्टूबर, 2017, (ii) नवम्बर, 2017, (iii) दिसम्बर, 2017, (iv)जनवरी, 2018 में सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें 2.53 करोड़ बच्चों तथा 68 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीका प्रतिरक्षण प्रदान किया जाना है।
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	मार्च, 2017		• विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ। • यह परियोजना देश में बाढ़ की भविष्यवाणी और आवर्ती बाढ़ एवं सूखे की कमजोरी को कम करने की क्षमता में सुधार के लिए है। • गंगा और ब्रह्मपुत्र में जल विज्ञान परियोजना प्रथम व द्वितीय लागू किया जायेगा।
18.	स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत	22 अगस्त, 2017	केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेडकर ने किया।	• इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विघालय के 12 लाख से अधिक छात्रों के स्वास्थ्य और तन्दुरूस्ती कार्ड बनाया जाना निर्धारित किया गया है।
19.	मेंटर इंडिया अभियान योजना	23 अगस्त, 2017	नीति आयोग द्वारा प्रारंभ	• अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में देशभर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिकरिंग लैबों में छात्रों के मार्गदर्शन के काम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल करके यह राष्ट्र निर्माण की रणनीतिक पहल है। • मेंटर इंडिया अभियान का लक्ष्य अटल टिंकरिंग लैब के प्रभाव को अधिकतम बनाना है। • यह सम्भवत: विश्वभर में औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रसार के अभियान की पहल है।

(Continued)

तालिका 14.1: केन्द्रीय योजनाएं, परियोजनाएं तथा कार्यक्रम/मिशन (Continued)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	केन्द्रीय विषय/मंत्रालय	प्रमुख तथ्य
20.	शादी-शगुन योजना	अगस्त, 2017	केन्द्रीय अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन के तहत शुरू की गयी है।	• मुस्लिम लड़कियों एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 51,000 रूपये की राशि बतौर शादी-शगुन देने का फैसला किया है। • योजना का मकसद मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना है। • 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं को 10 हजार रूपये वजीफा दिया जायेगा। • इस राशि की हकदार वही लड़कियाँ होगी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की होगी। • इस योजना के अन्तर्गत मुस्लिम के अतिरिक्त सिख, ईसाई, पारसी और जैन धर्म से सम्बन्धित व्यक्ति भी लाभ प्राप्त कर सकते है।
21.	सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना	13 अक्टूबर, 2017		• ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना का शुभारंभ किया। • योजना का प्राथमिक उद्देश्य सम्पूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना है। • योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गावं (न्यूनतम 100 आवास के लिए) को चिन्हित किया जायेगा। • प्रत्येक पॉलिसी से कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा के साथ चिन्हित गांव के सभी घरों को कवर करने का प्रयास किया जायेगा। • सांसद अदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी गांव इसकी सीमा में लाये जायेंगे।
22.	सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)	25 सितम्बर, 2017		• 16,320 करोड़ रूपये की इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को नि:शुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रूपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। इसका लक्ष्य दिसम्बर 2018 के अन्त तक देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाना है।
23.	दीनदयाल स्पर्श योजना	03 नवम्बर, 2017 को संचार मंत्री और रेलवे मंत्री द्वारा लागू किया गया जिसकी शुरूआत 14 नवंबर, 2017 से की गई।		• केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने टिकटों के संग्रहण तक पहुंच बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति की एक विशेष योजना दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की। • इस योजना के अन्तर्गत 6 से 10 कक्षा तक के विद्यार्थियों को डाक टिकट संग्रहण को एक रूचि के रूप के विकसित करने के लिए 500 रूपये प्रतिमाह की दर से (6000 रूपये प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति दी जायेगी।

तालिका 14.2: बजट 2018-19 में घोषित प्रमुख नई योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रमुख तथ्य
1.	ऑपरेशन ग्रीन	• केन्द्र सरकार ने फल-सब्जियाँ उगाने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरूआत करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिद दामों में उपलब्ध हो सकेंगे। • इस कार्य के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। • ऑपरेशन ग्रीन किसान उत्पादन संगठनों, कृषि समीरतंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यवसायिक प्रबन्धन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। • ऑपरेशन फ्लड की तरह इस योजना से फल सब्जी उत्पादकों को लाभ होगा।
2.	ग्रामीण कृषि बाजार बनाने की योजना	• 86 प्रतिशत से ज्यादा लघु और सीमान्त किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत किया जायेगा। • 22 हजार ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियों ($APMC_s$) के उन्नयन हेतु 2 हजार करोड़ रूपये की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष के स्थापना की घोषणा की गयी है।
3.	टॉप योजना	• यह योजना वर्तमान में मुख्य रूप से तीन कृषि उत्पादों टमाटर, प्याज एवं आलू के लिए है।
4.	आयुष्मान भारत योजना	• केन्द्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना है। इसके तहत प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जायेगा। **स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्रः** • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गयी है। • ये 1.5 लाख केन्द्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लायेंगे। ये स्वास्थ्य केन्द्र मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध करायेंगे। • ये केन्द्र आवश्यक दवाईयां और नैदानिक सेवा भी मुफ्त उपलब्ध करायेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। • इन केन्द्रों को अपनाने के लिए सीएसआर और लोकोपकारी सस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया है। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजनाः** • आयुष्मान भारत के तहत इस दूरगामी योजना की पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की जायेगी। जिसके तहत द्वितीय और तृतीय देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रूपये प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जायेगा। • यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थकेयर योजना होगी, जिससे देश की 40 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर हो जायेगी।
5.	मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा कोष की स्थापना	• इन दोनों कोषों की स्थापना के लिए बजट 2018-19 में 10 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गये है।
6.	राइस (Revitalising Infrastructure and Systems in Education – RISE)	• आगामी 4 वर्षों (वर्ष 2022 तक) में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने हेतु 1 लाख करोड़ रूपये के साथ RISE नामक पहल की घोषणा की गयी। इस पहल का वित्तीयन उच्चत्र शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी (HETA) द्वारा किया जायेगा।
7.	पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन	• बांस को हरित सोने की संज्ञा दी गयी है। इस मिशन के तहत बांस को वन के स्थान पर घास का दर्जा दिया जायेगा ताकि किसानों विशेषकर उत्तर पूर्वी किसानों की आय बढ़ायी जा सकेगी। इस मिशन के लिए 1290 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।